www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 अपराधियों से निपटने में विफल नीतीश...

3 जोधपुर बांसवाड़ा जोन की समीक्षा बैठक, अधिकारी...

4 ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कमी नहीं रहने देगी...

वर्ष: 9 | अंक: 249 | दिल्ली, गुरुवार, 3 जुलाई 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र से मिले धन का इस्तेमाल करने में विफल रही: नड्डा

हिमाचल प्रदेश (एजेन्सी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने बुधवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार केंद्र से जारी धनराशि खर्च नहीं कर पाई और लोगों के साथ अन्याय कर रही है। बिलासपुर में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने आए नड्डा ने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आपदा राहत कोष जारी किया है और स्वास्थ्य सेवा के लिए करोड़ों रुपये जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन सबके बावजूद राज्य अभी तक उस पैसे का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। नड्डा ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस जनविरोधी है और उसे जनता से कोई लगाव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सत्ता हथियाकर पैसे जुटाना है। इससे पहले नड्डा ने राजीव बिंदल को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी।

उत्तराखंड में ट्रक के पलट जाने से तीन कांवड़ियों की मौत

उत्तराखंड (एजेन्सी)। टिहरी जिले में बुधवार को कांवड़ियों को ले जा रहे एक ट्रक के पलट जाने से उसपर सवार तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 18 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। नरेंद्र नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से 21 कांवड़ियों का समूह उत्तरकाशी जिले के हर्षिल जा रहा था और इस दौरान यह दुर्घटना हो गई। मृतकों की पहचान विक्की, सुनील सैनी और संजय के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम ने ट्रक के अगले हिस्से में फंसे चार साल के बच्चे की जान बचा ली।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ पशुपालन विभाग के काम की समीक्षा की

जम्मू-कश्मीर (एजेन्सी)। केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को यहां केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज संयुक्त रूप से पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू जिले के सतवारी में स्थित 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दूध संयंत्र का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज जम्मू के सतवारी में स्थापित 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले अति उच्च तापमान वाले दूध संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने प्रगतिशील डेयरी किसानों से बातचीत की, जिन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से बेहतर आय और संगठित खरीद के अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय मंत्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। सिन्हा ने एक्स पर कहा, आज श्रीनगर स्थित राजभवन में केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जी से मिलकर खुशी हुई।

नए आपराधिक कानूनों से न्याय के प्रशासन में सिर्फ भ्रम पैदा हुआ: चिदंबरम

नई दिल्ली (एजेन्सी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि तीन नए आपराधिक कानून बनाने की कवायद निरर्थक थी और इससे न्यायाधीशों, वकीलों और पुलिस समेत न्याय के प्रशासन में केवल भ्रम पैदा हुआ है। चिदंबरम ने यह भी दावा किया कि नए अधिनियम ज्यादातर कॉपी एंड पेस्ट वाले हैं और कुछ ही नए प्रावधान जोड़े गए हैं। उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमन को स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा सुधार करार दिए जाने के एक दिन बाद आई है। शाह ने इस बात पर जोर दिया था कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने नए कानून - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के सभी अधिकार सुरक्षित हैं और कोई भी अपराधी दंड से बच नहीं सकेगा। सरकार पर निशाना साधते हुए कि चिदंबरम ने कहा कि उसने बार-बार दावा किया है कि तीन आपराधिक कानून आजादी के बाद सबसे बड़े सुधार हैं, जबकि यह बात सच्चाई से कोसों दूर है। पूर्व गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने तीन विधेयकों की जांच करने वाली स्थायी संसदीय समिति को एक असहमति नोट भेजा था, और यह संसद में पेश की गई रिपोर्ट का हिस्सा है। उन्होंने कहा, मेरे असहमति नोट में संबंधित नए विधेयक के साथ आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा दर धारा की तुलना करने के बाद मैंने दावा किया था कि आईपीसी का 90-95 प्रतिशत, सीआरपीसी का 95 प्रतिशत और साक्ष्य अधिनियम का 99 प्रतिशत हिस्सा कॉपी करके दिया गया है और संबंधित नए विधेयक में पेस्ट कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी को घाना के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया

संजना भारती/पीआईबी

घाना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके प्रतिष्ठित शासन कौशल और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया।

घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने प्रधानमंत्री मोदी को बुधवार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

मोदी ने सम्मान स्वीकार करते हुए कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से यह पुरस्कार विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। उन्होंने इस सम्मान को दोनों देशों के युवाओं की आकांक्षाओं और उज्ज्वल भविष्य, घाना और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों तथा उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं एवं विविधता को समर्पित किया। उन्होंने कहा, यह सम्मान एक जिम्मेदारी भी देता है और वह जिम्मेदारी भारत-घाना मित्रता को और मजबूत बनाने के लिए काम करने की है।

भारत घाना के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और एक भरोसेमंद दोस्त एवं विकास में भागीदार के रूप में योगदान देना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री को उनके प्रतिष्ठित शासन कौशल और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस विशेष सम्मान के लिए घाना के लोगों और सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा, दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य और परंपराएं इस साझेदारी को पोषित करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच मित्रता को और गहरा करता है तथा उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की नयी जिम्मेदारी सौंपता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, मोदी ने विश्वास जताया कि घाना की उनकी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा भारत-घाना संबंधों को नयी गति प्रदान करेगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, यह भारत-घाना के बीच गहरे और दीर्घकालिक संबंधों का प्रमाण है। इससे पहले, मोदी और महामा के बीच बुधवार को व्यापक वार्ता होने के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक विस्तार दिया। प्रधानमंत्री मोदी की घाना की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है और तीन दशकों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली घाना यात्रा है।

विकसित दिल्ली निर्माण में सबका साथ जरूरी: रविन्द्र इंद्राज

दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए हर महीने लगाएंगे कैम्प: मंत्री

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुधवार को व्हीलचेयर वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संगम विहार और गिरी नगर के गरीब एवं वंचित परिवारों के दिव्यांग बच्चों और अन्य लोगों को 50 व्हीलचेयर वितरित की गईं। कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली, सफदरजंग द्वारा आस्था एनजीओ और दिल्ली स्टडी ग्रुप के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री श्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने इस आयोजन के लिए महिला क्लब का उत्साह बढ़ाया और कहा कि दिल्ली सरकार विकसित दिल्ली लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसके लिए हर वर्ग और हर संस्था का साथ जरूरी है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार हर महीने की 10 तारीख को एक जिले में सहायक उपकरण वितरण कैम्प लगाएगी। जहां कोई भी आकार कैम्प का लाभ ले सकेगा। सामाजिक कार्यकर्ता शोभा तुली ने दिल्ली को समावेशी और सभी के लिए सुलभ बनाने को लेकर अपने सुझाव दिए।

इस अवसर पर भाजपा नेता श्री विजय जॉली, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डॉ. रवि गुगनानी, रोटेरियन टीना कपूर, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सतेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता शोभा तुली, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रोटेरियन संजीव वाधवा, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन रोटेरियन नीरज भटनागर, असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन मधुमती, विशेषज्ञ श्री टी.डी. धरियाल उपस्थित रहे।

सीएम सैनी ने मॉनसून सीजन को लेकर की तैयारियों की समीक्षा

समाधान शिविरों के दौरान प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें उपायुक्त-सीएम

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौजूदा मॉनसून सीजन के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ड्रेनों की पूरी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से बचने के लिए प्रभावी जल निकासी प्रणाली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बरसाती पानी के त्वरित निकासी के लिए पर्याप्त संख्या में पंपों की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों में बारिश के पानी की निकासी के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने उपायुक्तों को जलभराव के संभावित स्थानों की पहचान कर तदनुसार उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में उपलब्ध पंपों की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पंपों को पूरी तरह चालू स्थिति में रखा जाए ताकि वर्षा जल की निकासी में कोई समस्या न हो। साथ ही उन्होंने सभी उपायुक्तों को अपने जिलों में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के पास उपलब्ध पंपों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका समुचित उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त निर्धारित प्रारूप में पंपों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पंप सेटों की निर्बाध संचालन के लिए बिजली बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ड्रेनों की सफाई की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विशेष रूप से नगरों एवं शहरों से गुजरने वाले ड्रेनों की समुचित सफाई की जाए ताकि ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न न हो सके। उन्होंने फरीदाबाद में गौंछी ड्रेन को कवर करने की संभावना तलाशने और राज्य की अन्य ड्रेनों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ड्रेनों का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए और जाल लगाकर इनमें कचरा डालने से रोका जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सड़कों, पुलों के निर्माण तथा जल निकासी के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि बाढ़ की तैयारियों के लिए प्रत्येक जिले को 4.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, जल निकासी कार्यों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 50 लाख रुपये दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को मानसून सीजन के दौरान दूषित पानी के कारण होने वाली तथा वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए उपयुक्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों के दौरान प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में आवेदन खारिज किया जाता है, वहां जनता की संतुष्टि के लिए आवेदक को स्पष्ट और विशिष्ट कारण बताए जाएं।

दिल्ली को 'ग्लोबल क्रिएटिव कैपिटल' के रूप में सॉफ्ट पॉवर के रूप में विकसित करने का प्रयास: कपिल मिश्रा

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली अब केवल सत्ता का केंद्र ही नहीं बल्कि रचनात्मकता का नया माइलस्टोन बनने की राह पर अग्रसर है। कला, संस्कृति, फिल्म, संगीत, फैशन डिजाइनिंग, साहित्य और पत्रकारिता इत्यादि में नवाचार के हर आयाम को सशक्त मंच देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 'क्रिएटिव कैपिटल' की अवधारणा को साकार रूप देने में जुटी है।

इसी क्रम में दिल्ली सचिवालय में पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने एक उच्चस्तरीय राउंड टेबल मीटिंग की। यह सम्मलेन दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग और क्रिएटिव इकोनॉमी फोरम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस चर्चा में कपिल मिश्रा के साथ क्रिएटिव इकोनॉमी फोरम की संस्थापक सुप्रिया सूरी भी मौजूद रहीं। बैठक का मुख्य उद्देश्य था- दिल्ली के लिए एक दूरदर्शी रचनात्मक नीतिगत ढांचा तैयार करना, जिसमें क्रिएटिव इकॉनमी को राजधानी के विकास का मुख्य आधार बनाया जाए।

बैठक में यह विचार विमर्श किया गया कि कैसे दिल्ली को क्रिएटिव बिजनेस हब में बदला जाए जिससे न केवल स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिले बल्कि रोजगार और वैश्विक साझेदारियों के नए अवसर भी उत्पन्न हों। इस पहल के तहत ऐसे नीति परिवर्तनों पर चर्चा हुई जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें और युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

मीटिंग में क्रिएटिव क्षेत्रों से आये विशेषज्ञों ने तमाम विचार माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा के समक्ष रखे जिसमें दिल्ली के पारंपरिक खान-पान को एक मंच देने के लिए दिल्ली फूड फेस्टिवल आयोजित किया जाए और साथ ही साहित्य प्रेमियों के लिए लिट्रेचर फेस्टिबल का भी आयोजन हो। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले स्मारकों में कार्यक्रम आयोजित किए जायें ताकि दिल्ली के समृद्ध इतिहास से लोगों का साक्षात्कार कराया जा सके।

वहीं दिल्ली के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित की जायें और बदलते वक्त में अक को पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समायोजित किया जाए, टैलेंट हंट के माध्यम से दिल्ली और देश के टैलेंट को दिल्ली सरकार प्रोत्साहन देकर उसे नई दिशा दे, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिहाज से संसाधन विकसित किए जायें और दिल्ली के अनछुए पहलुओं को फिल्मिंग करके सोशल मीडिया में डाला जाए ताकि 'ब्रांडिंग दिल्ली' का विजन धरातल पर उतर सके।

कुलदीप सिंह धालीवाल ने सी. आर. पाटिल को अजनाला में रावी दरिया के कारण बाढ़ से हुए नुकसान और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए फंड देने की विनती की

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। एन. आर. आई. मामलों के मंत्री स. कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल के साथ रावी दरिया, जोकि पंजाब के अमृतसर के अजनाला जिले में से होकर बहता है और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सरहद बनाता है, सम्बन्धी महत्वपूर्ण चिंता के मामले पर मुलाकात की। उन्होंने पंजाब सरकार को जरुरी फंड देने की विनती की। यह फंड हमारी जमीन की सुरक्षा, हमारे सुरक्षा बुनियादी ढांचे की रक्षा और इस संवेदनशील सरहद पर गैर-कानूनी गतिविधियों के बढ़े हुए जोखिम को रोकने के लिए जरुरी प्रोजेक्टों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मंत्री ने कहा कि भारी बाढ़ के समय के दौरान अजनाला में रावी के साथ लगते क्षेत्रों को काफी नुक्सान होता है। इसमें न सिर्फ हमारे किसानों की कीमती कृषि योग्य जमीन का नुक्सान होता है, बल्कि महत्वपूर्ण फौज और बी. एस. एफ. चौकियों को भी भारी नुक्सान होता है। यह नुक्सान हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी सीमा सुरक्षा बलों की संचालन क्षमता को सीधा प्रभावित करता है। इसके इलावा, इन सरहदी इलाकों में बाढ़ों के कारण होने वाला विघ्न बदकिस्मती से नशों की तस्करी की संभावनाओं को बढ़ाता है, जो हमारे राज्य और राष्ट्र के लिए एक गंभीर खतरा है।

धालीवाल ने केंद्रीय मंत्री को आगे बताया कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से कंट्रोल करने और घटाने के लिए यह जरूरी है कि हम नदी के इस हिस्से के साथ-साथ महत्वपूर्ण सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा उपाय करें। इसमें मजबूत बाढ़ नियंत्रण बुनियादी ढांचा और सरहदी सुरक्षा प्रतिष्ठानों को मजबूत करना शामिल होगा।

दिल्ली में बड़े स्तर पर होगा रोजगार मेले का आयोजन: मिश्रा

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली सचिवालय में विधि एवं न्याय, श्रम, रोजगार, विकास, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। यह बैठक माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित विभागीय समीक्षा बैठक की तैयारी के क्रम में आयोजित की गई।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं में दिल्ली सरकार की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। विभागों से उनके आगामी कार्ययोजना और योजनाओं की समयबद्ध पूर्णता को लेकर जानकारी ली गई। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इस समीक्षा बैठक में कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा 'टैलेंट हंट योजना' की शुरूआत पर चर्चा हुई जिसका उद्देश्य दिल्ली के युवाओं में छिपी प्रतिभाओं की खोज और उन्हें मंच प्रदान करना है। इसके साथ ही विकास विभाग की प्रमुख योजना के तहत घुम्मनहेड़ा गाँव में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल गौशाला की स्थापना के प्रस्ताव पर पर भी बैठक में चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में दिल्ली के समग्र विकास के लिए 'पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉप-अप योजना' के तहत किसानों को 3000 (तीन हजार) रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। श्रम विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना तथा रोजगार मेला आयोजित करने की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाए इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा कई योजनाएं प्रस्तुत की गईं।

इन परियोजनाओं में सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक बोट टूर आयोजित करना, ब्रांडिंग दिल्ली और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना, पर्यटन क्षेत्र में युवाओं के लिए फेलोशिप कार्यक्रम, दिल्ली को फिल्म निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और प्रधानमंत्री संग्रहालय को जोड़ने वाला एक नया पर्यटन सर्किट विकसित करना और शीतकालीन महोत्सव का वार्षिक आयोजन शामिल है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, खाद्य उत्सव आदि होंगे।

सम्पादकीय

मध्यमवर्गीय परिवार नहीं फंसे ऋण के जाल में

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी की है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड कम्पनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी की घोषणा करना प्रारम्भ कर दिया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कमी का लाभ शीघ्र ही भारत में ऋणदाताओं तक पहुंच सके एवं इससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। भारत में चूंकि अब मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में आ गई है, अतः आगे आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में और अधिक कमी की जा सकती है। इस प्रकार, बहुत सम्भव है ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी के बाद कई नागरिक जिन्होंने पूर्व में कभी बैंकों से ऋण नहीं लिया है, वे भी ऋण लेने का प्रयास करें। बैंक से ऋण लेने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस ऋण को चुकता करने की क्षमता भी ऋणदाता में होनी चाहिए अर्थात ऋणदाता की पर्याप्त मासिक आय होनी चाहिए ताकि बैकों द्वारा प्रदत्त ऋण की किश्त एवं ब्याज का भुगतान पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके। इस संदर्भ में विशेष रूप से युवा ऋणदाताओं द्वारा क्रेडिट कार्ड के उपयोग पश्चात संबंधित राशि का भुगतान समय सीमा के अंदर अवश्य करना चाहिए क्योंकि अन्यथा क्रेडिट कार्ड एजेंसी द्वारा चूक की गई राशि पर भारी मात्रा में ब्याज वसूला जाता है, जिससे युवा ऋणदाता ऋण के जाल में फंस जाते हैं। बैकों से लिए गए ऋण की मासिक किश्त एवं इस ऋणराशि पर ब्याज का भुगतान यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो चूककर्ता ऋणदाता से बैकों द्वारा दंडात्मक ब्याज की वसूली की जाती है। इसी प्रकार, कई नागरिक जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं एवं इस क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की गई राशि का भुगतान यदि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं कर पाते हैं तो इस राशि पर चूक किए गए क्रेडिट कार्ड धारकों से भारी भरकम ब्याज की दर से दंड वसूला जाता है। कभी कभी तो दंड की यह दर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच रहती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले नागरिक कई बार इस उच्च ब्याज दर पर वसूली जाने वाली दंड की राशि से अनभिज्ञ रहते हैं। अतः बैंकों से ली जाने वाली ऋणराशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का समय पर भुगतान करने के प्रति ऋणदाताओं को सजग रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह ऋणदाताओं के हित में है कि वे बैंक से लिए जाने वाले ऋण की राशि तथा ब्याज की राशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का पूर्व निर्धारित एवं उचित समय सीमा के अंदर भुगतान करें क्योंकि अन्यथा की स्थिति में उस चूककर्ता नागरिक की क्रेडिट रेटिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आगे आने वाले समय में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है एवं बहुत सम्भव है कि भविष्य में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त ही न हो सके। ऋणदाता यदि किसी प्रामाणिक कारणवश अपनी किश्त एवं ब्याज का बैंकों अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को समय पर भुगतान नहीं कर पाता है और उसका ऋण खाता यदि गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित हो जाता है तो इस संदर्भ में चूककर्ता ऋणदाता द्वारा बैकों को समझौता प्रस्ताव दिए जाने का प्रावधान भी है। इस समझौता प्रस्ताव के माध्यम से चूककर्ता ऋणदाता द्वारा सम्बंधित बैंक अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को मासिक किश्त एवं ब्याज की राशि को पुनर्निर्धारित किए जाने के सम्बंध में निवेदन किया जा सकता है। परंतु, यदि ऋणदाता ऋण की पूरी राशि, ब्याज सहित, अदा करने में सक्षम नहीं है तो चूक की गई राशि में से कुछ राशि की छूट प्राप्त करने एवं शेष राशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में अदा करने के सम्बंध में भी समझौता प्रस्ताव दे सकता है। ऋण की राशि अथवा ब्याज की राशि के सम्बंध के प्राप्त की गई छूट की राशि का रिकार्ड बनता है एवं समझौता प्रस्ताव के अंतर्गत प्राप्त छूट के चलते भविष्य में उस ऋणदाता को बैकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान चूककर्ता ऋणदाता को रखना चाहिए। अतः जहां तक सम्भव को ऋणदाता द्वारा समझौता प्रस्ताव से भी बचा जाना चाहिए एवं अपनी ऋण की निर्धारित किश्तों एवं ब्याज का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भुगतान करना ही सबसे अच्छा रास्ता अथवा विकल्प है। भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के चलते मध्यमवर्गीय नागरिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिनके द्वारा चार पहिया वाहनों, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एवं मकान आदि आस्तियों को खरीदने हेतु बैकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा रहा है।

जयंती

हंसा मेहता

जन्म: 3 जुलाई, 1897; मृत्यु: 4 अप्रॅल, 1995) एक समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के रूप में भारत में काफी प्रसिद्ध रही हैं। इनके पिता मनुभाई मेहता बड़ौदा और बीकानेर रियासतों के दीवान थे। हंसा मेहता का विवाह देश के प्रमुख चिकित्सकों में से एक तथा गाँधीजी के निकट सहयोगी जीवराज मेहता जी के साथ हुआ था। भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इन्होंने संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हंसा मेहता इन्हीं में से एक थीं।

पुण्यतिथि

मोहम्मद उस्मान

जन्म-15 जुलाई, 1912, आजमगढ़; शहादत-3 जुलाई, 1948) भारतीय सेना के एक उच्च अधिकारी थे, जो भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध (1947-48) में शहीद हुए। उस्मान 'नौशेरा के शेर के' रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। वह भारतीय सेना के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और साहसी सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने जम्मू में नौशेरा के समीप झांगर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे।

कल मिलेंगे

टीचर स्टूडेंट से-ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे?
स्टूडेंट-चिड़िया बनकर.
टीचर-तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा?
स्टूडेंट-जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

अपराधियों से निपटने में विफल नीतीश सरकार देगी हथियार लाइसेंस

मुख्यमंत्री नीतीश का यह फैसला दर्शाता है कि बिहार में कानून-व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। बिहार पुलिस हिंसक अपराध के मामलों में आई तेजी है। बिहार में पिछले 10 वर्षों में राज्य में फर्जी शस्त्र लाइसेंस, अवैध बंदूक और गोला व बारूद की अनाधिकृत तौर पर बिक्री बढ़ी है और यह प्रदेश में बढ़ रही हिंसा की बड़ी वजह है। राज्य के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस दिशा में एक अध्ययन भी किया है

-योगेंद्र योगी

राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे बेशक राज्य का चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो। बिहार जैसा प्रदेश जो एक दौर में नस्लवाद और जातीय हिंसा के लिए कुख्यात रहा, अब भी अपराधों के मामले में पीछे नहीं हैं। बिहार में सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, अपराधों से सभी का गहरा रिश्ता रहा है। बिहार में कानून-व्यवस्था हमेशा से एक चुनौती रही है। हालात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इसका सरकार ने आसान विकल्प खोज लिया है। वह यह है कि अब मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जैसे जनप्रतिनिधि आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रख सकेंगे। जिससे लगभग ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को फायदा मिलेगा। राज्य के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आवेदनों की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश जारी किया है। बिहार में आगामी चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है।

बिहार सरकार ने यह फैसला राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं के कारण लिया है। इसके विपरीत सच्चाई यही है कि ऐसा करके नीतीश सरकार ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को साधने की कोशिश की है। यदि नीतीश कुमार के इस फैसले को पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के हित में भी माना जाए तब यह प्रदेश में अपराध की हालत को दर्शाता है। जिस प्रदेश में जनप्रतिनिधी ही सुरक्षित नहीं हैं, वहां आम अवाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। सवाल यह भी है कि लाखों की संख्या में हथियारों के लाइसेंस देने से क्या राज्य में हिंसा में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। बिहार में यदि पुलिस तंत्र प्रभावी और मजबूत होता तो यह नौबत नहीं आती कि लाखों जनप्रतिनिधियों को हथियारों के लिए लाइसेंस दिया जाए। इससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के बजाए हथियारों के लाइसेंस देने का आसान विकल्प चुना है। बड़ा सवाल यह भी है कि जनप्रतिनिधी अपनी सुरक्षा हथियारों से कर लेंगे, किन्तु प्रदेश की अवाम का क्या होगा।

मुख्यमंत्री नीतीश का यह फैसला दर्शाता है कि बिहार में कानून-व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। बिहार पुलिस हिंसक अपराध के मामलों में आई तेजी है। बिहार में पिछले 10 वर्षों में राज्य में फर्जी शस्त्र लाइसेंस, अवैध बंदूक और गोला व बारूद की अनाधिकृत तौर पर बिक्री बढ़ी है और यह प्रदेश में बढ़ रही हिंसा की बड़ी वजह है। राज्य के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस दिशा में एक अध्ययन भी किया है। बिहार पुलिस ने यह अध्ययन बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार को सुपर्द किया। पुलिस ने राज्य में हिंसक अपराधों में वृद्धि को सीधे तौर पर राज्य में अवैध हथियारों और गोला-बारूद की बढ़ती बिक्री से जोड़ा है और हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती, लूट, बैंक डकैती और सड़क डकैती जैसे अपराधों के लिए इसे जिम्मेदार माना है। एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो) के अनुसार, बिहार 2017 से 2022 के बीच हिंसक अपराधों के मामले में लगातार शीर्ष पांच राज्यों में शुमार रहा है। इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि प्रति वर्ष पटना में 82 हिंसा के मामले औसतन रूप से सामने आए हैं और राज्य की राजधानी हिंसा की राजधानी बन चुकी है। पटना के बाद क्रमशः मोतिहारी में 49.53, सारण 44.08), गया 43.50, मुजफ्फरपुर 39.93 और वैशाली में 37.90 मामले प्रति वर्ष औसतन दर्ज किए जा रहे हैं। हिंसक अपराधों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 10 जिलों में पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालंदा और बेगूसराय शामिल हैं। ये उन शीर्ष 10 जिलों में से भी हैं जिनमें सबसे अधिक आर्म्स एक्ट के मामले हैं। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अवैध आग्नेयास्त्र और हिंसक अपराध के मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध है। एक दशक के अपराधों के अध्ययन के आधार पर विशेष कार्य बल ने बिहार के डीजीपी से सिफारिश की है कि वे व्यक्तिगत गोला-बारूद कोटा को मौजूदा 200 से घटाकर न्यूनतम कर दें। साथ ही यह भी सिफारिश की गई है कि डीजीपी कार्यालय आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने में असमर्थ मानता है, उनके लाइसेंस रद्द कर दे। लाइसेंस प्राप्त मिनीगन कारखानों की निगरानी करें। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में अपराधों के मामलों में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश रहा। इसके बाद अपराधों के पायदान पर क्रमशः केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार है। अपराधों की श्रेणी में चोरी के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर डकैती और उत्पीडन के मामले सामने आए। अपराधों में आंकड़ों के लिहाज से तीसरे नंबर बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में चिंता की बात यह है कि इसमें वर्ष 2023 के मुकाबले 1.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जबकि अपहरण के मामलों में पिछले वर्ष के मुकाबले 5.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में क्रमशः 13.05 प्रतिशत और 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में दर्ज सभी मामलों में से घरेलू हिंसा के लिए सबसे ज्यादा 4,889 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद दहेज उत्पीडन (787), यौन उत्पीडन (116), दूसरी शादी (81), मोबाइल/साइबर से जुड़े अपराध (59), बाल विवाह (24), कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन (22), मानव तस्करी (12), दहेज हत्या (5) और अन्य (1,297) दर्ज किए गए। 2021-22 में 86 प्रतिशत दर्ज मामलों का निपटारा किया गया, जबकि 2020-21 में यह 82 प्रतिशत था। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आंकड़े और आबादी के आधार पर दावा किया है कि 2004 के मुकाबले 2025 में अपराध में भारी गिरावट आयी है। लालू सरकार के काल खंड से तुलना करते हुए डीजीपी ने कहा कि 20-21 साल पहले सालाना 500- 1000 फिरौती के लिए अपहरण के मामले दर्ज होते थे। अब यह आंकड़ा 50 के आसपास है। डकैती के मामलों में भी पहले 1200 से अधिक वार्षिक घटनाएं होती थीं, जो अब घटकर 150 के करीब पहुंच चुकी हैं। गौरतलब है कि बिहार पहले से ही भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम रहा है। लालू सरकार के चारा और जमीन के बदले में रेलवे में नौकरी को लेकर लालू यादव जेल में हैं। नीतीश कुमार से उम्मीद थी कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराधों में सुधार होगा। किन्तु जिस तरह हथियारों की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बिहार का भविष्य उज्जवल नजर नहीं आता।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

बड़ी चुनौती है फैक्ट्री के धमाकों को रोकना

श्रम और रोजगार मंत्रालय के महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत के पंजीकृत फैक्ट्रियों में दुर्घटनाओं के कारण हर दिन औसतन तीन मजदूरों की मौत हुई है और 11 घायल होते हैं। नवंबर 2022 में आरटीआई जवाब के अनुसार, भारत में रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में हर साल होने वाली दुर्घटनाओं में 1,109 वर्करों की मौत हो गई और 4,000 से अधिक वर्कर घायल हुए

-अशोक मधुप

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पासमैलारम फेज एक इलाके में एक केमिकल फैक्टरी में हुए विस्फोट में 34 कर्मचारियों की मौत हो गई। तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना फेस वन क्षेत्र स्थित डी-93 सेक्टर-दो स्थित शाम पेंट इंडस्ट्रीज केमिकल की कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि लपटें आसमान तक छूती नजर आई। करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड टीम ने इस आग की घटना में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान न होने की बात कही है। इसी 16 जून को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी से करीब दो किलोमीटर दूर यह फैक्ट्री चार महिलाओं की मौत हो चुकी थी। नौ घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि फैक्ट्री संचालक ने पटाखे बनाने के लिए आसपास की रहने वाली महिलाओं को कम मजदूरी पर रखा था। उन्हें केवल 300 रुपये दिहाड़ी दी जाती थी। मजदूरों को न कभी ट्रेनिंग दिलाई और नही आपातस्थित से निपटने का कोई प्रशिक्षण दिया गया। फैक्ट्री में दुर्घटनाएं होने पर कुछ दिन शोर मचता है। मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा होने के बाद सब शांत हो जाता है। दुर्घटनाएं रोकने की कोई योजना नही बनती। नहीं फैक्ट्री के श्रमिकों को दुर्घटना होने के समय की चुनौती बताई जाती हैं। दुर्घटना होने के समय की चुनौती के समय के लिए प्रशिक्षित भी नही किया जाता। दुर्घटना होने पर क्या किया जाए इसका भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। फैक्ट्री लगती है किंतु उनका तकनीकि निरीक्षण नहीं होता। निरीक्षण करने वाली अधिकारी पैसे के बल पर अपने आफिस में ही बैठकर रिपोर्ट बना देते है। सही मायने में फैक्ट्रियों में होने वाली दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौत का जिम्मेदार वह अमला भी है जो समय-समय पर इनके सुरक्षा तंत्र का निरीक्षण करता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत के पंजीकृत फैक्ट्रियों में दुर्घटनाओं के कारण हर दिन औसतन तीन मजदूरों की मौत हुई है और 11 घायल होते हैं। नवंबर 2022 में आरटीआई जवाब के अनुसार, भारत में रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में हर साल होने वाली दुर्घटनाओं में 1,109 वर्करों की मौत हो गई और 4,000 से अधिक वर्कर घायल हुए। ये 2017 से 2020 के बीच आंकड़ों के आधार पर है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह संख्या और भी ज्यादा है क्योंकि बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्रों में होने वाले हादसों की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की जाती है।

निदेशालय जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट, 2022 के अनुसार 2021 में, महाराष्ट्र में 6,492 खतरनाक फैक्ट्रियों में से केवल 1,551 का निरीक्षण किया गया, जिससे 23.89 प्रतिशत निरीक्षण दर प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, 39,255 पंजीकृत फैक्ट्रियों में से केवल 3,158 का निरीक्षण किया गया। इससे 8.04 प्रतिशत निरीक्षण मिली। अन्य प्रमुख औद्योगिक राज्यों में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। तमिलनाडु में सामान्य निरीक्षण दर 17.0 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों की निरीक्षण दर 25.39 प्रतिशत थी। गुजरात में सामान्य निरीक्षण दर 19.33 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों की निरीक्षण दर 19.81 मिली। 2021 के लिए अखिल भारतीय आंकड़े सामान्य निरीक्षणों के लिए 14.65 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों के लिए 26.02 प्रतिशत थे। उपर्युक्त विवरण से लिया गया है।

खराब निरीक्षण दरों का एक कारण कर्मचारियों की कमी है। महाराष्ट्र में निरीक्षकों की नियुक्ति दर केवल 39.34 प्रतिशत थी। इसमें 122 स्वीकृत अधिकारियों में से केवल 48 कार्यरत थे। गुजरात में नियुक्ति दर 50.91 प्रतिशत रही, तो तमिलनाडु में यह 53.57 प्रतिशत थी। अखिल भारतीय नियुक्ति दर 67.58 प्रतिशत थी। स्वीकृत पदों की संख्या पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या के सापेक्ष वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त रही है। 2021 में, अखिल भारतीय स्तर पर 953 स्वीकृत निरीक्षकों में से प्रत्येक को वार्षिक रूप से 337 पंजीकृत फैक्ट्रियों का निरीक्षण करना पड़ता है।

मई 2024 में, महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक मीडिया रिपोर्ट में स्वीकार किया कि सुरक्षा निरीक्षण और प्रमाणन अक्सर ऑडिटरों और फैक्ट्री मालिकों या प्रबंधकों के बीच "समझ" के आधार पर किए जाते थे। यह संकेत देता है कि नियोक्ता भी श्रम निरीक्षकों के समान ही दोषी हैं, और भ्रष्ट प्रथाओं की "आपूर्ति पक्ष" को संबोधित करना "मांग" पक्ष के सुधार के समान ही महत्वपूर्ण है।

प्रदेश स्तर पर विशिष्ट सीमा मात्रा के साथ खतरनाक रसायनों और ज्वलनशील गैसों की एक सूची स्थापित की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य को प्रमुख खतरे वाले कार्यस्थलों की सूची बनाए रखनी चाहिए। समें सुविधा का प्रकार, उपयोग किए गए रसायन और संग्रहीत मात्रा का विवरण हो। खतरनाक सामग्री की सूची और इन्वेंट्री को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहीत करें, जिस तक नियामक निकाय, आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता, और जनता आसानी से पहुंच सकें। निरीक्षण प्रणाली को उदार बनाने के बजाय, सरकारों को आईएलओ सम्मेलन के प्रावधानों का पालन करके मजबूत श्रम बाजार शासन सुनिश्चित करना होगा। प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति और खतरनाक और रासायनिक पदार्थों के उपयोग को देखते हुए, सख्त निरीक्षणों की आवश्यकता है।

औद्योगिक आपदाओं की पुनरावृत्ति सरकार की विफलता को दर्शाती है कि उसने पिछले घटनाओं से सबक नहीं सीखा है। सुधारों और कमजोर शासन के नाम पर, राज्य अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता कि वह एक सुरक्षित कार्य और जीवन सुनिश्चित करे। एक प्रभावी और नैतिक श्रम निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सार्थक सुधारों की आवश्यकता है जो श्रमिकों और समुदाय की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही फैक्ट्री श्रमिकों का आपदा के समय सुरक्षा के उपाए, कैसे बचाव करें आदि का बार-बार प्रशिक्षण देना होगा। सभी उद्योगों के निरीक्षण के लिए तकनीकि विशेषज्ञों की टीम बनानी होगी। उन्हें नियमित निरीक्षण के निर्देश करने होंगे। इससे किसी दुर्घटना होने पर मौत और घायलों का आंकड़ा कम किया जा सकता है। दुर्घटना होने के हालात में इन तकनीकी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी फिक्स करनी होगी। देखने में आ रहा है कि निरीक्षण स्टाफ की फेक्ट्री स्वामियों से मिलीभगत होने के कारण उद्योग स्वामी प्रायः प्रशिक्षित स्टाफ नही रखते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के अगवानपुर की दुर्घटना ग्रस्त पटाखा फैक्ट्री का भी ये ही कारण रहा। फैक्ट्री स्वामी ने सस्ते के चक्कर में फैक्ट्री के आसपास रहने वाली महिलाएं रख रखी थी। उन्हें वह मात्र तीन सौ रूपया रोज मजदूरी देता था। उनकी सामजिक सुरक्षा आदि का भी प्रबंध नही था।

केंद्र ही नहीं प्रदेश सरकारों को भी उद्योग स्वामियों को बताना होगा कि उनके यहां काम करने वाले श्रमिक और तकनीकि विशेषज्ञ देश की धरोहर है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उद्योग के साथ देश और समाज की भी है। घटना होने पर मात्र जांच के आदेश और मुआवजा देने से ही काम नही चलेगा। दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी भी तै करनी होगी। जिम्मेदार लोगों को दंडित भी करना होगा तभी जाकर ये दुर्घटनाएं रूकेगी। एक बात और यदि उद्योग में सुरक्षा मानक कड़े हों, उद्योग श्रमिकों को समय-समय पर सुरक्षा संबधी प्रशिक्षण मिले तो दुर्घटनाएं ही न हों। हों तो मौत और घायलों की संख्या बहुत कम रहे। दुर्घटनाएं न हो तो उद्योग भी न मरे। दुर्घटनाएं होने से श्रमिकों के साथ एक प्रकार से संबधित उद्योग भी मर जाता है। अधिकतर दुर्घटनाग्रस्त उद्योग के स्वामी दुर्घटना के कारण हुए नुकसान, श्रमिकों को मुआवजा आदि देने के कारण बर्बाद हो जाते हैं। वे दुबारा से मुश्किल से ही काम को जोड़ पाते हैं। इससे देश का एक व्यापारी, एक व्यवसायी भी एक प्रकार से मर जाता है। उसका आर्थिक रूप से मरना देश की प्रगति को भी नुकसान देता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

भारत, घाना संबंधों को व्यापक साझेदारी तक ले जाएंगे: प्रधानमंत्री मोदी

(एजेन्सी)।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के बीच बुधवार को व्यापक वार्ता होने के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक विस्तार दिया।

वार्ता के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने अगले पांच वर्षों में दोतरफा व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और भारत घाना की विकास यात्रा में न केवल भागीदार है, बल्कि सह-यात्री भी है। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक मोदी के पश्चिम अफ्रीकी देश की राजधानी पहुंचने के कुछ घंटे बाद हुई। मोदी पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचे हैं। दोनों पक्षों ने संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

महामा की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्रपति महामा और मैंने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है तथा इस खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया।

मोदी ने कहा, हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में घाना के सहयोग के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया और यूरोप में संघर्षों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और बातचीत एवं कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान तलाशने का आह्वान किया। मोदी ने कहा, यह युद्ध का युग नहीं है, समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए विस्फोट में चार सरकारी अधिकारियों की मौत

(एजेन्सी)।
पाकिस्तान। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को हुए बम धमाके में एक सहायक आयुक्त समेत चार सरकारी अधिकारियों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। अफगानिस्तान की सीमा से सटे आदिवासी जिले बाजौर में खार तहसील के मेला मैदान के पास हुए इस विस्फोट में नवागई तहसील के सहायक आयुक्त फैसल सुल्तान के वाहन को निशाना बनाया गया।

अन्य मृतकों की पहचान सहायक उपनिरीक्षक नूर हकीम, तहसीलदार वकील खान और सिपाही रशीद के रूप में हुई है। सुरक्षाबलों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है, तलाशअभियान और हमले की जांच जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार बैरिस्टर सैफ ने बम विस्फोट की निंदा करते हुए इसे बेहद दुखद घटना बताया। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, सहायक आयुक्त और तहसीलदार सहित अहम लोगों की मृत्यु बेहद दुखद है। उन्होंने कहा, हम देश विरोधी तत्वों को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। सैफ ने कहा कि मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।

नोवाक जोकोविच ने जीत दर्ज कर दूसरे दौर में बनाई जगह

(एजेन्सी)।
सर्बियाई दिग्गज और महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेट की समस्या के बाद चार सेट तक चले मैच में जीत दर्ज कर ली। इसके साथ ही जोकोविच ने टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बनाई, लेकिन तीन बार ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट और तीसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव और महिला वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ पहले ही दौर से बाहर हो गए। जोकोविच को पहले दौर के मैच में पेट की समस्या के कारण दो बार डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी लेकिन आखिर में वह एलेक्जेंडर मुलर को 6-1, 6-7, 6-2, 6-2 से हारने में सफल रहे।

रिकॉर्ड 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ने बाद में कहा कि, मैं 45 मिनट तक पेट की समस्या से परेशान रहा, लेकिन डॉक्टर्स की चमत्कारिक गोलियों से मैं अपनी ऊर्जा वापस पाने में सफल रहा। ज्वेरेव को पहले दौर में 72वीं रैंकिंग वाले आर्थर रिंडरक्नेच से पांच सेटों में चार घंटे 40 मिनट में 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4 से हार का सामना करना पड़ा। रिंडरक्नेच का ऑल इंग्लैंड क्लब में 1-4 का करियर रिकॉर्ड था और वह ग्रैंड स्लैम टूनामेंटों में 18 बार तीसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

पिछले साल विम्बलडन और इस साल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनलिस्ट रहे सातवें नंबर के खिलाड़ी लोरेंजो मुसेट्टी भी पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें निकोलोज बेसिलशविली ने बाहर का रास्त दिखाया। दुनिया में 126वें नंबर के खिलाड़ी और यहां क्वालीफायर बेसिलशविली अपने पिछले 31 ग्रैंड स्लैम टूनामेंटों में केवल एक बार चौथे दौर तक पहुंच पाए हैं।

वहीं मंगलवार को उलटफेर का दौर जारी रहा और महिला एकल में खिताब की प्रबल दावेदार गॉफ भी पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाई। उन्हें दयाना यास्त्रेम्स्का ने 7-6, 6-1 से हराया। इस तरह से विंबलडन में पहले दो दिन में 23 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी दूसरे दौर में पहुंचने में असफल रहे। दूरे दिन बाहर होने वाले वरीयता प्राप्त पुरुष खिलाड़ियों में 18वें नंबर के उगो हम्बर्ट, 27वें नंबर के डेनिस शापोवालोव, 28वें नंबर के अलेक्जेंडर बुब्लिक और 30वें नंबर के एलेक्स मिशेलसन शामिल थे।

जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देने पर भड़के रवि शास्त्री, गिल-गंभीर को जमकर सुनाया

(एजेन्सी)। बुधवार को भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में तीन बदलाव किए हैं। शार्दुल ठाकुर, साई सुदर्शन को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। जसप्रीत बुमराह की जगह आकाशदीप को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री बुमराह के ना होने से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि बुमराह दूसरे टेस्ट में खेलें, क्योंकि दोनों मैचों के बीच लगभग एक सप्ताह का अंतर था। बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के कारण बुधवार से शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच में आराम दिया गया। वह लीड्स में पहले टेस्ट मैच में खेले थे जिसमें भारत पांच विकेट से हार गया था।

घी, साबुन और स्नैक्स होंगे सस्ते?

(एजेन्सी)।
केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ढांचे में जल्द ही महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाला से बताया गया है कि चर्चा के तहत एक प्रमुख प्रस्ताव यह है कि या तो कुछ आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया जाए या 12% स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में 12% जीएसटी लागू करने वाली अधिकांश वस्तुएं आम नागरिकों द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं। इनमें वे उत्पाद शामिल हैं जो मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उपभोग पैटर्न में प्रमुखता से शामिल हैं।

विचाराधीन योजना में इन वस्तुओं को 5% के निचले कर स्लैब में पुनः वर्गीकृत करना शामिल है, जिससे वे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी रूप से सस्ती हो जाएँगी। वैकल्पिक रूप से, सरकार 12% स्लैब को पूरी तरह से खत्म करने और वस्तुओं को मौजूदा निचले या उच्च स्लैब में पुनः आवंटित करने का विकल्प चुन सकती है। जीएसटी परिषद की आगामी 56वीं बैठक में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। प्रोटोकॉल के अनुसार, परिषद की बैठक बुलाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना आवश्यक है, लेकिन सूत्रों से संकेत मिलता है कि सत्र इस महीने के अंत में हो सकता है।

यह कदम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है, खासकर चुनाव से पहले के वर्ष में, और आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद, जिसमें राज्य वित्त मंत्री शामिल हैं, के पास कर दरों में बदलाव की सिफारिश करने का अधिकार है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो यह 2017 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू होने के बाद से जीएसटी दरों में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक होगा।

सिनेमा को मिलने जा रही है नयी जोड़ी!

(एजेन्सी)। मारुति द्वारा निर्देशित प्रभास की अगली फिल्म द राजा साहब ने पहले से ही काफी उत्साह पैदा कर दिया है। हॉरर-कॉमेडी में प्रभास एक मजेदार और नए किरदार में हैं और प्रशंसकों को उनका लुक और टीजर काफी पसंद आ रहा है। पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा निर्मित इस फिल्म में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी मुख्य भूमिका में हैं। लेकिन अब, इससे भी बड़ी चीज की योजना बनाई जा रही है-और यह सभी का ध्यान खींच रही है। कुछ महीने पहले, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि करीना कपूर प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की कॉप एक्शन ड्रामा स्पिरिट में अभिनय करेंगी, लेकिन यह खबर झूठी निकली। नवीनतम और सनसनीखेज चर्चा से पता चलता है कि करीना, प्रभास की एक और फिल्म में नजर आएंगी। यहां चर्चा का विषय 'द राजा साहब' है। टीम एक स्पेशल सॉन्ग फिल्माना चाहती है और कथित तौर पर, वे इसके लिए करीना कपूर खान को लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि निमार्ताओं ने बी-टाउन की इस अभिनेत्री से बातचीत शुरू कर दी है और उन्हें मोटी रकम देने की पेशकश भी की है। करीना इस तेलुगु रोमांटिक हॉरर कॉमेडी का हिस्सा बनने के लिए सहमत होती हैं या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। इससे पहले, 3 इडियट्स की अभिनेत्री ने कुछ खास गानों में जलवे बिखेरे थे, जिन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। मारुति द्वारा निर्देशित, द राजा साब का निर्माण टीजी विश्व प्रसाद द्वारा पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले किया जा रहा है। थमन धुनों की रचना कर रहे हैं।

जोधपुर बांसवाड़ा जोन की समीक्षा बैठक, अधिकारी फिल्ड में रहे, बारिश से सड़क खराब हो तो तत्काल सही करवाये: उप मुख्यमंत्री

एसबी संवाददाता

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिये है बरसात के मौसम में सड़के खराब होती है तो उन्हें तत्काल ठीक करवाया जाये ताकि आमजन को परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करे की बारिश की वजह से रोड खराब होने से यातायात बाधित न हो, अधिकारी फिल्ड में रहकर इसकी मॉनिटरिंग करें।

उप मुख्यमंत्री बुधवार को शासन सचिवालय में जोधपुर जोन प्रथम एवं बांसवाड़ा जोन की सड़क एवं अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिये आयोजित बैठक को संबोधित कर रही थी। गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री के निदेर्शों की पालना में पीडब्ल्यूडी के कार्यो की प्रगति के लिये हर सप्ताह जोनवार समीक्षा बैठक आयोजित जा रही है।

उपमुख्यमंत्री ने जोधपुर, पाली, सिरोही, फलोदी, जालौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों की सड़क परियोजनाओं की प्रगति की माइक्रो लेवल पर समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में राह सुगम करने हेतु बनाये जा रहें अटल पथों के साथ नाली जरूर बनाई जाये। उन्होंने बरसाती मौसम को ध्यान रखते हुए सड़को की रिपेयर और सड़क किनारे जंगल सफाई के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2024-25 के कामों को शीघ्र पूरा करवाने एवं बजट घोषणा 2025-26 के घोषित कामों की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर काम शुरू करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने वन, भूमि विवाद या अन्य कारणों से लंबित परियोजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि विभाग के अधिकारी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इन लंबित कामों को शीघ्र पूरा करवाये।

पांच सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देनी होगी: उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये है कि अधिकारी आगामी बैठक में यह बतायेगे कि इस अवधि में उन्होंने कितनी फील्ड विजिट की और निरीक्षण के दौरान जो खामियां मिली उनमें कितना सुधार करवाया। उन्होंने आगामी पांच सप्ताह बाद उक्त जोन की आयोजित होने वाली बैठक तक वे सभी काम पूरे करवाने के निर्देश दिये है, जिनके संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

इस दौरान उपमुख्यंमत्री ने जोधपुर जोन प्रथम एवं बांसवाड़ा में चल रही एनएचएआई, एनएच, आरएसआरडीसी, राजस्थान स्टेट हाईवे आथोरिटी, पेचेबल व नॉन पेचेबल तथा मिसिंगलिंक सहित विभिन्न श्रेणी की सड़कों की समीक्षा की।

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी श्री प्रवीण गुप्ता, मुख्य अभियंता टी.सी गुप्ता सहित मुख्यालय एवं संबंधित जिलों के अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।

राज्य कंट्रोल रूम में नियुक्त अधिकारी व संपर्क सूत्र:

अशोक जांगिड़-9414548109
जतिन दायमा-6375558012
कृष्ण कुमार मीणा-7891720742

इन अधिकारियों को कंट्रोल रूम का इंचार्ज नियुक्त किया गया है। आमजन इन नंबरों पर संपर्क कर अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करवा सकेंगे।

जिला स्तर पर भी बनाए गए कार्यालय: केवल राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि हर जिले में भी स्थानीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जिससे समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उपमुख्यमंत्री ने ज़िलाधिकारियों व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे फील्ड विज़िट कर स्वयं हालात की समीक्षा करें।

मोहिंदर भगत ने बागवानी क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार फसली विविधता को प्रोत्साहित कर और किसानों की आय बढ़ाकर बागवानी क्षेत्र के विस्तार तथा राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बागवानी पहलों की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु, बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने आज पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बागवानी निदेशक श्रीमती शैलेन्द्र कौर ने मंत्री को बागवानी को प्रोत्साहित करने तथा किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं और पहलों से अवगत कराया। उन्होंने फसल उत्पादकता को और बेहतर बनाने, उन्नत तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने और बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चल रहे प्रोजेक्ट्स की जानकारी साझा की। मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता शिविरों और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से नवीनतम तकनीकों, सरकारी योजनाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं की नियमित जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए।

प्रदेश में अपराधियों को लेकर मुख्यमंत्री सैनी सख्त: डॉ. अरविंद शर्मा

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है। आपराधिक घटनाओं को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यहां तक कि पुलिस के आला अधिकारियों को इस विषय में विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। खुद पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर भी अपराध नियंत्रण को लेकर निगरानी कर रहे हैं। डॉ. अरविंद शर्मा आज गोहाना में एक निजी प्रतिष्ठान में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अपराध को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश पुलिस ने आपराधिक घटनाओं पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चला रखा है और इसी कड़ी में पुलिस ने महज एक महीने के दौरान 58 ईनामी बदमाश, 101 गैंगस्टर व उनके सहयोगी व 178 जघन्य अपराध करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है।

डीएम की अध्यक्षता में हुई पीस कमेटी की बैठक

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इंतजार हुसैन बदायूं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने मोहर्रम व कांवड़ यात्रा के संदर्भ में पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पीस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जनपदवासी सभी त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे व सौहार्द के साथ मनाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भ्रामक व भड़काऊ सूचना फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि ताजिए की ऊंचाई व आकार का ध्यान रखा जाए क्योंकि यह आमजन की सहूलियत के दृष्टिगत आवश्यक है। वहीं उन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे की ऊंचाई का भी ध्यान रखने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत व तहसील स्तर पर पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी घटना या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें ताकि समय रहते उसका निदान कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि मोहर्रम व कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि मोहर्रम व कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस अवसर पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी, पीस कमेटी के सदस्य, गणमान्य लोग आदि मौजूद रहे।

राजस्थान नर्सिंग आफिसर के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने किया जार के पदाधिकारियों का स्वागत

संजना भारती संवाददाता टोंक। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की ओर से बुधवार को दोपहर दो बजे निजी शोरूम पर जार एसोसिएशन टोंक के पदाधिकारीयो का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे सभी जार एसोसिएशन के संरक्षक एस.एन. चावला, प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम जोशी, अध्यक्ष ब्रजेश परिडवाल, महासचिव रविन्द्र जौहरी, अशोक शर्मा आकाशवाणी, राजाराम गौतम, पीयूष गौतम, नासिर खान, सुरेन्द्र गुप्ता, कमलेश कुमार सैनी कार्यकारिणी सदस्य अरशद शाहीन, अनिल विजय सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

राजस्थान नर्सिंग आफिसर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने सबका आभार व्यक्त किया।

निदेशक ने ली समीक्षा बैठक, बजट घोषणाओं सहित विभिन्न योजनाओं को तय समयावधि में पूर्ण करने के दिए निर्देश

एसबी संवाददाता

जयपुर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मोदी ने बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय में बाल अधिकारिता, विशेष योग्यजन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि आमजन को सामाजिक सुरक्षा का संपूर्ण लाभ देने के लिए अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली में नवीनता और नवाचार की सोच विकसित करनी चाहिए। उन्होंने पेंशन और छात्रवृत्ति में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। मोदी ने विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का पावर पॉइंट के जरिए प्रस्तुतीकरण देखा। उन्होंने बजट घोषणाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों और इनमें शामिल कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि हर कार्य में समयबद्धता, गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

बैठक में अतिरिक्त निदेशक सुमन पवार, हरिसिंह मीना, वित्तीय सलाहकार श्रीमती अंजू सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उप निदेशक दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त निदेशक सुण्डाराम मीना, श्रीमती रीना शर्मा, अशोक कुमार, अरविन्द कुमार, चंद्रशेखर चौधरी सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

छौड़ाही में जदयू के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक

एसबी ब्यूरो

छौड़ाही (बेगूसराय)। प्रखंड एकंबा पंचायत में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष राम प्रकाश सहनी ने किया एवं कार्यक्रम का संचालन प्रखंड अध्यक्ष रामनरेश आजाद ने किया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जदयू जिला अध्यक्ष रूदल राय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में न्याय के साथ विकास कर रहे है।

सरकार में भी और संगठन में भी पिछड़ा अतिपिछड़ा, महिला वर्ग, युवा वर्ग, दलित शोषित पीड़ित की आवाज बनकर इस समाज का राजनीतिक विकास, समाजिक विकास और शैक्षणिक विकास कर रहे हैं। युवाओ के लिये राज्य में खेलो का विकास के लिए वर्ष 2024 में राज्य में नये खेल विभाग का गठन किया। खेल को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण खेल एकेडमी एवं खेल विश्वविद्यालय तथा सभी पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मैडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 367 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। इस वर्ष खोलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ जिसका जिम्बा बिहार सरकार को मिला और सफल आयोजन भी हुआ यह गौरव की बात है।

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने कहा कि 2005 के पहले महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके विकास पर कोई काम नही किया गया। 2005 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को रोजगार एवं आत्म निर्भर बनाने के लिए कई काम किये हैं और कार रहें हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से बिहार के प्रगति के साथ-साथ अपने परिवार की स्थिति को भी मजबूत कर रही है।

जदयू नेता बिहार प्रदेश राजनीतिक सलाहकार सदस्य डॉ. प्रवीण कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के सभी तबको का विकास किये हैं चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम,अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो या अतिपिछड़ा, दलित हो या महादलित, महिला एवं बुजुर्ग सभी के लिये काम कर रहें है। जदयू जिला प्रवक्ता अरुण कुमार महतो ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2023 में जातिगत आधार गणना कराई जिसमें लोगो की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली गई। जिसमें 94 लाख अत्यंत गरीब परिवार पाए गए जिसमे अपर कास्ट, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल है। इन लोगों को रोजगार हेतु लघु उद्यमी योजना के तहत दो लाख रुपये सहायता प्रदान की जा रही है।

कार्यक्रम में उपस्थित जदयू नेता तेतर साहनी, मीडिया सेल अध्यक्ष मोनू पटेल, किसान प्रकोष्ट प्रदेश महासचिव विकास कुशवाहा, बिपिन मिश्रा, मुकेश राय, युवा प्रखंड अध्यक्ष मो. शाकिब आलम, पूर्व मुखिया सुरेश राम, बीरबल ठाकुर, अमिताभ बच्चन पटेल सहित बुथस्तरीय कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री ने किया पौधारोपण, 'एक पेड़ मां के नाम अभियान' में ऊर्जा विभाग के कार्मिक भी देंगे योगदान

एसबी संवाददाता

जयपुर। एक पेड़ मां के नाम-हरयालो राजस्थान वृक्षारोपण महाभियान ' में ऊर्जा विभाग भी अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाएगा। मानसून के दौरान प्रदेशभर में विभाग की ओर से थर्मल इकाइयों, ग्रिड सब स्टेशनों, कार्यालय परिसरों आदि में वृहद् स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा।

ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने बुधवार को सेन्ट्रल पार्क में पौधारोपण के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से देशवासियों को प्रकृति से जोड़ने का महत्ती संकल्प लिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम-हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाभियान के माध्यम से प्रदेश को हरा-भरा बनाने में जन-जन से भागीदारी का आह्वान किया है।

नागर ने कहा कि ऊर्जा विभाग के कार्मिक अधिक से अधिक पौधे लगाकर शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देंगे। ऊर्जा मंत्री के साथ ही विभाग के कार्मिकों ने भी इस दौरान गुलमोहर, आम आदि के पौधे लगाए।

अजमेर विकास प्राधिकरण की अटल आवासीय योजना में आवेदन प्रारम्भ

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों का खुद के घर का सपना होगा साकार

एसबी संवाददाता

जयपुर। अजमेर विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित एवं महत्वाकांक्षी अटल आवासीय योजना चाचियावास का बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी एवं जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया का शुभारम्भ किया गया। आवासीय योजना में समाहित कुल 270 भूखण्डों में से 191 भूखण्डों के लॉटरी द्वारा आवंटन के लिए ऑनलाईन आवेदन आज से प्रारम्भ हुए। आवेदन करने की अंतिम दिनांक 31 जुलाई को रात्रि 11.30 बजे तक निर्धारित है। लॉटरी की सम्भावित दिनांक 21 अगस्त 2025 है।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने इस योजना को एक सार्वजनिक हित में लिया गया सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उन परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी जो वर्षों से उचित दर पर अपने स्वयं के घर के सपने को साकार नहीं कर पा रहे थे।

उन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण की प्रशंसा करते हुए कहा कि ?से प्रयासों से शहर का संतुलित और योजनाबद्ध विकास होने के साथ आमजन को आवासीय सुरक्षा का अधिकार भी सुनिश्चित होता है। साथ ही उन्होंने एडीए के अधिकारियों को पूर्व में प्रारंभ की गई पृथ्वीराज नगर एवं अन्य अधूरी आवासीय योजनाओं के विकास को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इससे पहले से नियोजित योजनाओं को मूर्तरूप देकर जनहित में अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकेगा।

राज्य के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अटल आवासीय योजना चाचियावास में स्थित है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अजमेर विकास प्राधिकरण पुष्कर क्षेत्र में और भी योजनाएं विकसित करने के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करे।

उन्होंने कहा कि एडीए द्वारा पुष्कर क्षेत्र में की गई कुछ पूर्ववर्ती योजनाएं जैसे कि सूरजकुंड में इकोलॉजिकल फार्म हाउस योजना तथा होकरा गांव में प्रस्तावित रिजॉर्ट योजना सराहनीय रही हैं। ये योजनाएं क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती हैं।

श्री रावत ने यह भी सुझाव दिया कि कानस गांव में एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकास की प्रस्तावित योजना गति देनी चाहिए। पुष्कर जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के पास यदि विवाह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ?सी योजनाएं विकसित होने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

एडीए आयुक्त श्रीमती नित्या के. ने बताया कि रेरा पंजीकृत उक्त योजना चाचियावास ग्राम के समीप अजमेर-सीकर मुख्य सड़क से एक किलोमीटर दूरी एवं पुष्कर-जयपुर मुख्य सड़क से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर शहर के विभिन्न प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों के समीप अवस्थित है। आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त यह योजना नवीन अजमेर के आमजन की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। राजस्थान नगरीय विकास (भूमि निष्पादन) नियमन 1974 के नियमों के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों का श्रेणीवार आरक्षण यथा सरकारी कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति व जनजाति, मान्यता प्राप्त पत्रकार, दिव्यांगजन, निराश्रित और भूमिहीन एकल महिला व ट्रांसजेंडर का प्रावधान रखा गया है।

उन्होंने बताया कि लॉटरी द्वारा आवंटन किए जाने वाले भूखण्डों को आय वर्ग के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मानक शिक्षा के लिए की गयी पहलकदमियों के आ रहे हैं सकारात्मक नतीजे: हरजोत सिंह बैंस

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मानक शिक्षा प्रदान करने की वचनबद्धता के अंतर्गत किये जा रहे यत्नों स्वरूप पंजाब ने नेशनल ऐचीवमैंट सर्वे (एन. ए. एस.) 2024 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुये सर्वोच्च स्थान हासिल किया है।

एन. ए. एस. विद्यार्थियों की शैक्षिक प्राप्तियों का मूल्यांकन करने के लिए भारत का सबसे भरोसेमन्द और प्रतिष्ठित सर्वेक्षण है। इसमें समूचे शिक्षा नतीजों का मूल्यांकन करने के लिए तीसरी, छटी और नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। एन. ए. एस. (परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण) में पंजाब की प्रभावशाली रैंकिंग पर खुशी प्रकटाते हुये स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब ने तीसरी कक्षा की रैंकिंग में 80 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश (74) और केरला (73) को पछाड़ कर पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने आगे बताया कि छटी कक्षा के लिए पंजाब और केरला 67-67 अंकों के साथ सांझे तौर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। इसके साथ ही 9वीं कक्षा की रैंकिंग में पंजाब ने 57 अंकों के साथ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पछाड़ कर पहला स्थान हासिल किया।

एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग के साथ दिसंबर 2024 में यह देश व्यापक सर्वेक्षण करवाया गया जिससे सीखने के नतीजों का मूल्यांकन करने और आगामी सुधार वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जिसमें देश भर से हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। स. बैंस ने कहा कि एन. ए. एस. 2024 में पंजाब का शानदार प्रदर्शन मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के मानक शिक्षा को यकीनी बनाने और विद्यार्थियों के सीखने के नतीजों को बेहतर बनाने के प्रति समर्पण को दशार्ता है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार इस सफलता को जारी रखेगी और विद्यार्थियों को सबसे बढ़िया शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली के मानकों को और ऊँचा उठाने के लिए प्रयत्न जारी रखेगी।

स्कूल शिक्षा विभाग की शानदार प्राप्तियों पर रौशनी डालते हुये शिक्षा मंत्री स. बैंस ने बताया कि इस साल सरकारी स्कूलों के 845 विद्यार्थियों ने प्रभावशाली मुकाबले वाली राष्ट्रीय योग्यता- कम-प्रवेश परीक्षा (नीट) में क्वालीफायी किया जबकि 265 विद्यार्थियों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे. ई. ई.) मेनज सफलतापूर्वक पास की, जोकि विभाग की अकादमिक उत्कृष्टता को उत्साहित करने और देश की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को दशार्ती है। बताने योग्य है कि पंजाब सरकार के लिए शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।

जनसेवा ही भाजपा सरकार का संकल्प: जगमोहन आनंद

■ विधायक जगमोहन आनंद ने मुख्यमंत्री सैनी से की मुलाकात

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। विधायक जगमोहन आनंद ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में मुलाकात की और करनाल विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों तथा भविष्य की विकास योजनाओं को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायक जगमोहन आनंद को विश्वास दिलाया कि करनाल विधानसभा क्षेत्र के विकास की गति को और तेज किया जाएगा।

इस अवसर पर विधायक ने करनाल के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के साथ करनाल से जुड़ी जनसमस्याओं एवं आवश्यक मांगों के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अवगत करवाया, मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ इन विषयों को सुना और तत्क्षण संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। इस मौके पर विधायक जगमोहन आनंद ने करनाल की समूची जनता की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने करनाल के परिवारजनों को न केवल अपना अमूल्य समय दिया, बल्कि जो आत्मीयता, स्नेह और मान-सम्मान प्रदान किया, वह सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का करनाल वासियों से जुड़ाव केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके सुख-दुख में सहभागी बनने की जीवंत भावना है। उनका मार्गदर्शन और संरक्षण हमें निरंतर प्रेरित करता है।

इस अवसर पर चेयरपर्सन मेघा भंडारी, निगम पार्षद संकल्प भंडारी सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य उपस्थित थे।

वर्ल्ड बैंक की टीम ने सरस्वती नदी व रिवर रिचार्जिंग सिस्टम का किया दौरा

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा/ चण्डीगढ़। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि सरस्वती नदी के ऊपर कई जलाशय स्थापित किए हैं, जिनकी वजह से वॉटर लेवल बढ़ा है। पिछले 3 वर्ष से सरस्वती नदी में पानी चलने से किसान खुश हैं और गांव बोहली व ईसरगढ़ क्षेत्र के आस-पास के गांवो के लिए सरस्वती नदी वरदान साबित हो रही है। वर्ल्ड बैंक की टीम से लिड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डॉ जूप स्टाउटजिस्टिक और डॉक्टर बोगचन बेलनी स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल इरीगेशन और ड्रेनेज सिस्टम ने गांव बोहली व ईसरगढ़ में सरस्वती नदी व रिवर रिचार्जिंग सिस्टम का किया दौरा किया। उन्होंने बताया कि सरस्वती बोर्ड सरस्वती नदी को रिजर्व नेट करने के लिए लगा है। हमारा उद्देश्य सरस्वती नदी में 12 महीने पानी चलाने का है जो अभी छह से सात महीने तक पानी चलता है। सरस्वती बोर्ड आदिबद्री में एक डैम बैराज व एक बड़ा जलाशय बनाकर सरस्वती नदी में 12 महीने पानी चलाने के लिए प्रयासरत है और वह सपना दूर नहीं है जब जल्द ही 12 महीने सरस्वती में पानी चलेगा। श्री धूमन सिंह ने बताया कि सरस्वती नदी हमारी संस्कृति व सभ्यता है।

ब्रह्माकुमारीज आश्रम राजौंद ने नगर को हरा भरा करने का उठाया बीड़ा

■ एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत पौधारोपण अभियान चलाया

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार राजौंद। राजौंद के कैथल मार्ग पर स्थित ब्रह्माकुमारीज आश्रम द्वारा नगर को हरा भरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में दो जूलाई को "एक पेड़- मां के नाम" मुहिम के तहत गढ़ी पट्टी में पौधारोपण किया गया।

ब्रह्मकुमारी बहन आशा ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के मुहिम के तहत माता बहनों को जागरूक किया तथा पौधों के महत्व के बारे में बताया। अपने भेजे संदेश में राजयोगी भ्राता मेहर चंद ने कहा कि प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ निःशुल्क दिया, लेकिन आज मानव के उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति और औद्योगिकीकरण के कारण उसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है यदि अभी उसे संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमें ना तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, ना अन्य दूसरे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे। वास्तव में यह बाहरी प्रदूषण मानव मन के आंतरिक प्रदूषण का ही परिणाम है।

बीके नीलम व बीके सरीता ने अपने सन्देश में कहा कि आज खेतों में जो अन्न उपजा रहे हैं उसमें भी कीटों को मारने के उद्देश्य से जहरीली कीटनाशक दवाइयां डाली जा रही है जिससे अनाज भी विषैला और प्रदूषित हो रहा है। अतः प्रकृति को शुद्ध बनाने के लिए मन को शुद्ध बनाएं, प्रकृति के प्रति उदारता का भाव रखें। बीके ऊषा ने अपने संदेश में कहां कि ब्रह्माकुमारी संस्थान में हम राजयोग मेडिटेशन द्वारा पवित्र, शांति के प्रकंपन चारों ओर फैलाकर प्रकृति के पांचों तत्वों को सतोप्रधान बनाने का प्रयास करते हैं और हम सब के सामूहिक प्रयास से निश्चित रूप से भारत फिर से प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न, विश्व गुरु, सिरमौर बन जाएगा। एक वृक्ष, एक पुत्र के समान है हमें पौधों का संरक्षण अपनी संतान की तरह करना चाहिए क्योंकि संतान से बढ़कर प्रकृति हमारी सेवा करती है इस मुहिम मे भाई बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।

बीके आशा ने बताया कि राजौंद नगर को हरा भरा बनाने के आगे भी निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे। उन्होंने नगर के समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों भाई बहनों से अनुरोध किया कि ब्रह्मकुमारी आश्रम का नगर को हरा भरा बनाने में यथा संभव सहयोग करें। क्योंकि हम सबके प्रयास से ही हम अपने नगर को हरा भरा बना सकते हैं।

भिवानी में मनाई जाएगी गुरु दक्ष प्रजापति जयंती: रणबीर गंगवा

■ मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत, जयंती को लेकर लोगों में उत्साह: रणबीर गंगवा

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि आगामी 13 जुलाई को भिवानी में राज्य स्तरीय गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जयंती समारोह के सफल आयोजन को लेकर प्रदेश के कोने-कोने में जाकर निमंत्रण दिया जा रहा है और लोग बड़े उत्साह व ढोल-नगाड़ों के साथ जयंती समारोह में भारी संख्या में पहुंचेंगे।

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा बुधवार को स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस में आयोजित एक मीटिंग में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। करनाल आगमन पर मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का प्रजापति समाज द्वारा पुष्प गुच्छ देकर तथा पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रवीन लाठर, मेयर रेनू बाला गुप्ता तथा वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सुभाष बुम्बक प्रधान, रघुबीर गागट, रोशन लाल सामरा, कर्ण आजाद व अनिल चनालिया ने भी पुष्प गुच्छ के साथ कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने 13 जुलाई को भिवानी में मनाई जाने वाली गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह का न्योता दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महापुरुषों की जयंती को सरकारी कार्यक्रम के रूप में प्रदेश सरकार मना रही है, इन समारोहों को आयोजित करके महापुरुषों की जीवनी के बारे में जन-जन तक जानकारी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे हर समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकार ने जरूरतमंद, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया है। बैकलॉग के विभागों में पद खाली पड़े रहते थे, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद बैकलॉग की सीटों पर भर्तियों को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्तियों की दिशा और दशा को भी बदला है। युवाओं को अब बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरिट आधार पर नौकरियां मिल रही हैं।

इस मौके पर करनाल नगर निगम की मेयर रेनू बाला गुप्ता और भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रवीन लाठर ने सभी उपस्थित जनों को राज्य स्तरीय गुरु दक्ष प्रजापति जयंती का निमंत्रण दिया और मंत्री जी को विश्वास दिलाया कि करनाल से भारी संख्या में लोग जयंती में शिरकत करेंगे। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में करनाल जिले को प्रथम स्थान पर आने पर बधाई दी। इससे पहले मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस के सभागार में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित किया और पत्रकारों को भी राज्य स्तरीय गुरू दक्ष प्रजापति जयंती का निमंत्रण देते हुए कहा कि भिवानी में यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में 5 हजार किलोमीटर दूरी की सडकों को कारपेट करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, दिसंबर तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।

इस अवसर पर जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा, उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि धीरज खरकाली, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि सुरेंद्र उडाना, पूर्व चेयरमेन सतबीर वर्मा, करनाल धर्मशाला के प्रधान रामकुमार, सतीश सरोहा, धर्मवीर आर्य, विनोद डीग, नवीन प्रजापति, नरेश पबाना, मनीत प्रजापति, ओम प्रकाश, रामफल डाचर, पदम सिंह, विजय प्रजापति, दीपक, पवन, नरेंद्र, कृष्ण दत्त प्रजापति उपलाना, डॉ नरेश प्रजापति, जॉनी, महेन्द्र सरोहा, मंगतराम प्रजापति, बलबीर प्रजापति, राजेंद्र, गुरदयाल सहित भारी संख्या में समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मानवता जन शक्ति फाउंडेशन शिविर लगाकर कर रही जरूरतमंद लोगों की सेवा: प्रवीन राणा

■ स्वास्थ्य शिविर में 227 मरीजों ने कराई जांच, निशुल्क दवाईयां भी मिली

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। मानवता जन शक्ति फाउंडेशन द्वारा गांव पधाना में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अर्पणा हॉस्पिटल के अनुभवी डाक्टर्स, सग्गू डेंटल क्लीनिक नीलोखेड़ी द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर में पहुंचे 227 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और डॉक्टरों और संस्था के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। वहीं डॉक्टर्स की टीम द्वारा नेत्र रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, दंत रोग, व जनरल स्वास्थ्य की जांच की गई।

वहीं मरीजों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर व अन्य सभी टेस्ट निशुल्क किए गए और दवाईयां भी निशुल्क प्रदान की गई। शिविर में समाजसेवी एवं सरपंच प्रतिनिधि प्रवीन राणा ने संस्था के इस नेक कार्य की खुलकर प्रशंसा की और कहा कि मानवता जनशक्ति फाउंडेशन सही में मानवता के जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए उन्होंने फाउंडेशन के संस्थापक हरदीप राणा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसी जरूरतमंद व बीमार व्यक्ति के लिए इस तरह के कैंप लगाकर लोगों की सेवा करना सेवा धर्म का काम है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि हम सभी को इस नेक कार्य में भाग लेते रहना चाहिए ओर जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए।

इस अवसर पर संस्थापक हरदीप राणा, सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण राणा, अनाज मंडी तरावड़ी के प्रधान सुभाष गुप्ता, कुलदीप चौहान बिजना, राजबीर राणा, अनुराधा काम्बोज, सुजीता मान, नरेश चौहान, सरपंच आशीष राणा, उर्मिला टाया, सीमा पासवान, तम्मना बहल, कुलदीप राणा, धूम सिंह राणा, नैन सिंह, प्रदीप राणा कृष्ण दत शर्मा, रणधीर राणा, रविन्द्र ढुल,अनिल, गौरव आदि उपस्थित रहे।

वन विहार कार्यक्रम के तहत आरएसएस स्वयंसेवकों ने देहरादून और हरिद्वार का किया भ्रमण

एसबी विशेष संवाददाता करनाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक दिवसीय वन विहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करनाल माधव नगर के करीब 60 स्वयंसेवकों ने वन विहार कार्यक्रम के तहत देहरादून और हरिद्वार का भ्रमण किया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने ध्वज लगाकर शाखा लगाई। इसके बाद स्वयंसेवकों ने मस्ती के कार्यक्रमों में भाग लिया। देहरादून में सभी स्वयंसेवकों ने सहस्त्रधारा में स्नान किया। वन विहार कार्यक्रम की जानकारी देते हुए माधव नगर कार्यवाह भारत भूषण चुघ ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकताओं द्वारा हर वर्ष वन विहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी स्वयंसेवक मिलकर बाहर घूमने जाते हैं। इस दौरान खेलकूद इत्यादि के माध्यम से जहां उनका ज्ञानवर्धन होता है वहीं शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। कार्यक्रम के लिए एक माह से नगर कार्यकारिणी ने सभी बस्तियों में संपर्क किया गया और स्वयंसेवकों के रजिस्ट्रेशन किए गए। कार्यक्रम में लगभग 60 स्वयंसेवक शामिल हुए। उन्होंने बताया कि भगवा ध्वज के सामने स्वयंसेवकों ने शाखा लगाई। उन्होंने कहा कि वन विहार के दौरान सभी स्वयंसेवकों ने देहरादून के प्रमुख स्थानों को देखा और वापिस आते हुए हरिद्वार में भी गंगा में स्नान किया।

सह नगर कार्यवाह राजीव पोपली ने संगठन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस विजयदशमी से संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। सौ वर्ष होने के बावजूद संघ एक युवा शक्ति एवं सोच के साथ कार्य कर रहा है। इस शताब्दी वर्ष में अपने कार्य विस्तार के 6 बिंदु तथा पंच प्रण को पूर्ण करना है। इस दौरान उन्होंने सभी स्वयंसेवकों को गुरु पूजन और गुरु दक्षिणा के महत्व के बारे में बताया और इस उत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लेने की बात कही। वन विहार में सभी स्वयंसेवकों ने सामूहिक रूप से जलपान किया।

इस अवसर पर नगर कार्यवाह भारत भूषण, पवन देव, सुशील कुमार, वीरपाल, दिनेश गर्ग, सुनील, गोपाल व अशोक कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कमी नहीं रहने देगी नायब सरकार: कृष्ण लाल पंवार

एसबी संवाददाता चंडीगढ़। हरियाणा के विकास एवं पंचायत, भूगर्भ एवं खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नेतृत्व वाली राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कमी नहीं आने देगी।

श्री पंवार रोहतक के गांव काहनौर में पंचायत विभाग द्वारा बनाई गई गुर्जर चौपाल व आर.ओ. प्लांट का उद्घाटन करने के उपरांत सामुदायिक केंद्र में मौजूद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। गुर्जर चौपाल के निर्माण पर लगभग 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इसी प्रकार से लगभग 16 लाख रुपए की लागत से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर.ओ प्लांट लगाया गया है। उन्होंने गुर्जर चौपाल में शौचालय बनवाने के लिए 5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा सामुदायिक केंद्र में ए.सी. लगवाने के लिए अलग से 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बोर्ड परीक्षा में हरियाणा में दूसरे नंबर पर रहने वाली एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल काहनौर की छात्रा दिवांशी को 21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और स्कूल की निदेशक अनीता शर्मा को सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तीन कर्म के वे सभी रास्ते जो सिजरा में शामिल है, को पक्का किया जा रहा है।

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार की योजना के तहत प्रदेश के 250 गांवों में इंडोर जिम खोले जा चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि व्यायाम शालाओं का सुधारीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नायब सरकार ने प्रदेश के 19 हजार तालाबों का सुधारीकरण करने का निर्णय लिया है। इनमें 6000 गंदे तालाब है। पहले चरण में 2200 तालाबों का सुधारीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना के तहत हर गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहे हैं, जहां पर महिलाएं भजन-कीर्तन कर सकती हैं। ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के मद्देनजर भरे गांव में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो 20 साल से अधिक समय से गांव की फिरनी के अंदर रह रहा है, तो सरकार ने ऐसे गरीब व्यक्ति का मकान न तोड़ने का फैसला किया है। ऐसे व्यक्ति को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिलवाया जा रहा है। गांव की फिरनी को पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। श्मशान घाट व कब्रिस्तान की चारदीवारी व शेड लगाए जा रहे है।

श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे सभी गांव को महाग्राम योजना में शामिल किया है, जिनकी आबादी 15000 से ज्यादा है। महाग्राम योजना के तहत ऐसे गांवों का विकास करके शहरों जैसी सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के 5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के लोगों को योजना के तहत मकान प्रदान किए हैं। इसी प्रकार से 12 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की योजना के तहत हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध जल देने का काम किया जा रहा है।

रा. संस्कृत मॉडल सी. सै. स्कूल राजौंद में मिशन बुनियाद विद्यार्थियों के नहीं बनें बस पास, आईटी की कक्षा खाली, अविभावक परेशान

■ अविभावको ने सीएम, शिक्षा मंत्री, डीओ, बीओ, डायरेक्टर मिशन बुनियाद को लिखा पत्र

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार राजौंद। मिशन बुनियाद हरियाणा सरकार का सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली है। आठवीं कक्षा का विद्यार्थी तीन स्तरीय परीक्षा पास करके मिशन बुनियाद में दाखिला के योग्य होता है। मिशन बुनियाद का विद्यार्थी दो साल सरकार की योजना अनुसार मिशन बुनियाद में आनलाइन पढ़ कर सुपर सौ के लिए क्वालिफाई करता है।

सुपर सौ में चयनित विद्यार्थियों को नीट, मैडिकल, नोन-मैडिकल की तैयारी हरियाणा सरकार निशुल्क कुरुक्षेत्र में विकल्प फाउंडेशन के सहयोग से करवा रही है। जहां हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग मिशन बुनियाद व सुपर सौ के विद्यार्थियों का भविष्य संवारने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं राजौंद के शहीद सियाराम राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मिशन बुनियाद के विद्यार्थियों के स्कूल प्रिंसिपल विरेन्द्र सिंह द्वारा विद्यार्थियों को सहयोग नहीं किया जा रहा है। बताया गया कि मिशन बुनियाद के विद्यार्थियों के बस पास नहीं बनवाएं गए हैं। आज तक विद्यार्थियों का आईटी का पीरियड भी नहीं लगा है। जहां स्कूल प्रिंसिपल से हरियाणा सरकार की मिशन बुनियाद योजना में सहयोग की उम्मीद होती है। लेकिन सहयोग नहीं हो पा रहा है।

स्कूल प्रिंसिपल विरेन्द्र सिंह से जानकारी लेने के लिए मीडिया कर्मी स्कूल गए तो प्रिंसीपल सवा आठ बजे तक स्कूल में नहीं पहुंचे थे। फोन पर सम्पर्क किया गया तो प्रिंसिपल विरेन्द्र सिंह ने बताया कि मिशन बुनियाद के विद्यार्थियों का बस पास बनाने का कार्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजौंद व जिला शिक्षा अधिकारी कैथल का है। आईटी का पीरियड खाली होने पर प्रिंसिपल ने बताया कि मिशन बुनियाद के शिक्षकों की व्यवस्था करना खुद मिशन बुनियाद व सरकार का कार्य है। हम जितना हो सके सहयोग कर रहे हैं। अभिभावक ने स्कूल प्रिंसिपल से सकारात्मक सहयोग न मिलने पर इनकी शिकायत मुख्यमंत्री हरियाणा, शिक्षा मंत्री हरियाणा, उपायुक्त कैथल, जिला शिक्षा अधिकारी कैथल, उप-जिला शिक्षा अधिकारी कैथल, ब्लाक शिक्षा अधिकारी राजौंद, प्रदीप सैंसरवाल-डायरैक्टर मिशन बुनियाद, हरियाणा को की है। हरियाणा सरकार व उच्च अधिकारियों को अभिभावक ने लिखित शिकायत देते हुए बताया है कि ग्रीष्म अवकाश के बाद स्कूल शुरू हो चुकें हैं। लेकिन मिशन बुनियाद राजौद सैटर का कक्षा नौवीं के विद्यार्थीयों का आप्शनल विषय (आईटी) का परियड आज तक कभी नहीं लगा है। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश का गृह कार्य भी नहीं मिला था।

बताया गया कि मिशन बुनियाद खंड राजौंद का स्टडी सेंटर शाहिद सियाराम राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौंद में बनाया गया है। राजौंद के आसपास के गांव के विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रतिदिन राजौद में सरकारी व नीजि बसों द्वारा आना-जाना करते हैं। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल की उदासीनता के कारण विद्यार्थियों का आज तक बस पास नहीं बनाया गया है। जिससे प्रतिदिन बस परिचालकों से विद्यार्थियों का झगड़ा होता है। यदि विद्यार्थी परिचायक से लड़ झगड़ कर स्कूल में पहुंचेंगे तो वे अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से कैसे कर पाएंगे। अभिभावको ने हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग से सहयोग की अपील की है।

अवैध नशा मुक्ति केंद्र चलाने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजे जेल

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। गांव अजीमगढ में अवैध नशा मुक्ति केंद्र चलाने के मामले की जांच चौकी महमुदपुर प्रभारी एएसआई राजेश कुमार की टीम द्वारा करते हुए आरोपी गांव चाबा निवासी ईश्वर, भटिंडा पंजाब निवासी गौरव कुमार तथा समाना पंजाब निवासी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि डाक्टर नवराज सिंह डीएनओ कैथल की टीम द्वारा 1 जुलाई को गांव अजीमगढ में अवैध रुप से चलाए जा रहे एक नशा मुक्ति केंद्र पर रेड की गई। जहां पर अवैध रुप से बंदी बनाए गए 35 व्यक्तियों को रेस्क्यु करवाया गया। नशा मुक्ति केंद्र से बहुत सारी दवाईयां भी बरामद हुई है। जो प्रतिबंधित 42 नशीली गोलियां भी बरामद हुई है। सूचना उपरांत एएसआई राजेश कुमार की टीम मौके पर पहुंची जहां पर डीएनओ नवाराज सिंह ने उक्त तीनो व्यक्तियों व दवाईयों को पुलिस टीम को सौंपा। आरोपियों के खिलाफ थाना गुहला में मामला दर्ज कर लिया गया। तीनो आरोपी न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए।

सीजेएम ने किया नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का दौरा

एसबी संवाददाता कैथल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मैहला के आदेशानुसार बुधवार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव कंवल कुमार ने जिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र जिला नागरिक अस्पताल कैथल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां डॉक्टर सीमा मलिक से नशा मुक्ति / पुनर्वास केन्द्र में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और वहां पर भर्ती आठ मरीजों से भी बातचीत की। उन्होंने मरीजों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव कंवल कुमार ने बताया कि 12 जुलाई 2025 (शनिवार) को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत उपरोक्त अदालतों में लंबित मुकदमों में मोटर वाहन और पारिवारिक झगड़े के अतिरिक्त अन्य मामले शामिल हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने केस/विवाद का निपटारा लोक अदालत के माध्यम करवाना चाहता है तो वह संबंधित अदालत में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल में सम्पर्क कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं।